



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2010/आषाढ़ 1, 1932

No. 171]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2010/ASADHA 1, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क मन्त्रिदेशालय)

जांच शुल्कात संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2010

(मध्यमवधि समीक्षा)

विषय : चीनी ताइपेई से पेन्टाएरिथ्रिटॉल के आयातों के संबंध में प्रभावी पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मध्यमवधि समीक्षा जांच की शुरुआत।

सं. 15/10/2010-डीजीएडी.—यतः 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् पाटनरोधी नियम कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 5 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. 15/07/2006-डीजीएडी द्वारा चीनी ताइपेई (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पेन्टाएरिथ्रिटॉल (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अंतिम परिणाम अधिसूचित किए थे।

और यतः दिनांक 28 अप्रैल, 2008 की सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 55/2008-सी.शु. द्वारा निर्णायक समीक्षा में संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था।

2. मै. कनौरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया है, याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि इस तथ्य कि अंतिम जांच के बाद से पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में वास्तविक परिवर्तन हुआ है, को ध्यान में रखते हुए पूर्व में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क में संशोधन अपेक्षित है।

3. विचाराधीन उत्पाद.— विचाराधीन उत्पाद चीनी ताइपेई के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित पेन्टाएरिथ्रिटॉल है। पेन्टाएरिथ्रिटॉल एक अकार्बनिक रसायन है जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमा-शुल्क उपशीर्ष सं. 29054200 के तहत वर्गीकृत है। पेन्टाएरिथ्रिटॉल का प्रयोग एलकोयल रेजिन्स, रोजिन ईस्टर्स, प्लास्टिसाइजर्स, प्रिंटिंग स्याही, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक हेतु स्टेबलाइजर, मॉडिफाइड ड्राइंग ऑयल्स, डेटोनेटर, विस्फोटक, भेषज, कोर ऑयल तथा कृत्रिम स्नेहकों के विनिर्माण में होता है। यह उत्पाद भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार सीमा-शुल्क टैरिफ सं. 2905.42 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, ये सीमा-शुल्क तथा आईटीसी एचएस वर्गीकरण को बल सांकेतिक हैं और किसी भी प्रकार से मौजूदा जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

4. समीक्षा के आधार.—आवेदक ने दावा किया है कि मौजूदा शुल्क पाटन, जिससे क्षति हो रही है, की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे यह भी अनुरोध किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के बावजूद भारत में पाटित कीमतों पर इस उत्पाद का आयात जारी है। इन आयातों से मौजूदा स्तर पर भी अत्यधिक कीमत कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आगे आवेदक ने यह दावा किया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के बाद भी कीमत कटौती का स्तर अत्यधिक है जो इस बात का संकेत है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा अत्यधिक पाटन किया जा रहा है। पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री का सामना करना पड़ रहा है। यह दावा किया गया है कि शुल्क की मौजूदा मात्रा घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करने में असमर्थ रही है। अतः याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि इस शुल्क में समुचित परिवर्धन अपेक्षित है। याचिकाकर्ता ने आगे यह तर्क भी दिया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग अपने निष्पादन को बेहतर बनाने में असमर्थ रहा है और निरंतर जारी पाटित आयातों के कारण हुई क्षति की भरपाई हेतु मौजूदा शुल्क पर्याप्त नहीं है।

5. जाँच की शुरुआत.—सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत पाटनरोधी नियमों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करना अपेक्षित है। मै. कनोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. ने चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए एक याचिका दायर की है और ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं के अंतर्गत संबद्ध वस्तु पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क में संवर्धन/संशोधन हेतु अनुरोध किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुसार ऊपर उल्लिखित नियमावली के नियम 23 में निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत इस स्थिति में संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना समुचित होगा।

6. शामिल देश.—वर्तमान जाँच में शामिल देश चीनी ताइपेई है।

7. प्रक्रिया.—दिनांक 5-3-2008 की अधिसूचना संख्या 15/7/2006-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित अंतिम परिणामों की समीक्षा हेतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और दिनांक 28-4-2008 की अधिसूचना संख्या 55/2008-सीमा-शुल्क द्वारा अधिरोपित अंतिम शुल्क के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् प्राधिकारी इस बात की जाँच करने कि क्या सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और पाटनरोधी 1 नियमावली के अनुसार अपने मौजूदा स्वरूप और मौजूदा मात्रा में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक है, के लिए एतद्वारा समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं।

इस समीक्षा में दिनांक 5-3-2008 की अधिसूचना सं. 15/7/2006-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं।

8. जाँच की अवधि (पीओआई).—वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक है तथापि क्षति जाँच अवधि में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 और जाँच की अवधि शामिल होगी।

9. सूचना प्रस्तुत करना.—संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास/प्रतिनिधियों के जरिए उनकी सरकार, भारत में इस जाँच से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :—

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय

कमरा नं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

10. समय-सीमा.—इस जाँच से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो अगोपनीय रूपांतर सहित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए। तथापि, ज्ञात निर्यातकों और आयातकों जिन्हें अलग से पत्र भेजा जा रहा है, द्वारा उन्हें भेजे गए पत्र की तारीख से (40) चालीस दिन के भीतर सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

11. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण.—नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। ऐसे मामलों में जहाँ हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालते हैं तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2010

(Mid-Term Review)

Subject: Initiation of mid-term review investigation with regard to the anti-dumping duties in force involving the imports of Pentaerythritol from Chinese Taipei.

No. 15/10/2010-DGAD.— Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules), *vide* Notification No. 15/7/2006-DGAD dated 5th March, 2008, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) notified its final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of Pentaerythritol (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Chinese Taipei (hereinafter referred to as subject country).

And whereas, in the sunset review, the anti-dumping duty was imposed on the imports of subject goods *vide* Customs Notification No. 55/2008 Customs, dated 28th April, 2008.

2. M/s. Kanoria Chemicals & Industries Limited have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), the Petitioner has claimed that the anti-dumping duty imposed earlier is required to be reviewed in view of the fact that the dumping margin and injury margin have materially changed since the last investigation.

3. **Product under consideration.**—The product under consideration is Pentaerythritol originating in or exported from Chinese Taipei. Pentaerythritol is an organic chemical classified under Customs sub-heading No. 29054200 under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. Pentaerythritol finds application in manufacture of Alkyd Resin, Rosin Esters, Plasticizers, Printing Inks, Synthetic Rubber, Stabilizers for Plastics, Modified Drying Oils, Detonators, Explosives, Pharmaceuticals, Core Oils and Synthetic Lubricants. This product is classified under Customs Tariff heading no. 2905.42 as per Indian Trade Classification. The Customs and ITC HS classifications are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

4. **Grounds for Review.**—The applicant has claimed that the existing measure is no longer sufficient to counteract the dumping which is causing injury. It has been further submitted that the product continues to be imported into India at dumped prices, in spite of anti-dumping duty being in force. The imports are causing significant price undercutting even at the existing levels. The applicant has further claimed that price undercutting even after addition for the current anti-dumping duties is higher, which indicates intensive dumping by the exporters from the subject country. As a result of dumping, the domestic industry is faced with significant price underselling as well. It has been claimed that the quantum of the measure has not been able to address the injuries caused to the domestic industry. The petitioner has therefore argued that the measure is required to be suitably enhanced. The petitioner has further argued that domestic industry has not been able to improve its performance in spite of the existing anti-dumping duties and the existing measure is no longer sufficient to address injury being caused by continued dumped imports.

5. **Initiation.**—The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Anti-Dumping Rules made thereunder require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. M/s. Kanoria Chemicals & Industries Limited have filed a petition substantiating the need for mid-term review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Chinese Taipei and have requested for enhancement/revision of the anti-dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications. The Designated Authority considers that mid-term review of the anti-dumping duty recommended would be appropriate at this stage under the provisions laid down in Rule 23 of the Rules *supra*.

6. **Country involved.**—The Country involved in the present investigation is Chinese Taipei.

7. **Procedure.**—Having satisfied itself on the basis of evidence submitted by domestic industry for review of the final findings notified *vide* No. 15/7/2006-DGAD dated 5-3-2008 and final duty imposed by Notification No. 55/2008-Customs, dated 28-4-2008, the Authority hereby initiates investigations to review whether continued imposition of anti-dumping duties in the present form and to the present extent of duty is necessary in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Anti-Dumping Rules.

The review covers all aspects of Notification No. 15/7/2006-DGAD dated 5-3-2008.

8. Period of Investigation (POI).— The Period of Investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st January, 2009 to 31st December, 2009. The injury investigation period will however, cover the period 2005-06, 2006-07, 2007-08 and 2008-09 including the period of investigation.

9. Submission of information.— The exporters in the subject country and their government through their embassy/representatives in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are requested to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority,
Ministry of Commerce and Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

10. Time Limit.— Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within (40) forty days from the date of the letter addressed to them.

11. Inspection of public file.— In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

P. K. CHAUDHARY, Designated Authority